राजस्थान में इलेक्ट्रानिक की बोर्ड सुविधा

*5. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में कितने स्थानों पर इलेक्ट्रनिक की बोर्ड (ई.के.बी.) सुविधा उपलब्ध है;

(ख) गत तक वर्ष में उक्त मशीन कितने स्थानों पर कितनी-कितनी अवधि तक खराब रही;

(ग) डाक के द्वारा तार भिजवाने में अधिक से आधिक कितना समय लगा है; और

(घ) इस व्यवस्था में सुधार हेतु तत्काल कौन-कौन से उपाय किये जा सकते हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) जी हां। राजस्थान दुरसंचार सर्किल में 172 स्थान है जिनमें इलेक्ट्रनिक की बोर्ड (ईकेबी) सुविधा उपलब्ध है।

(ख) पिछले एक वर्ष में अलग-अलग अवधि के दौरान 172 स्थानों में से 23 स्थानिं पर मशीने खराब पड़ी थी। 8395(23*365) मशीन दिवसों में से 614 (7.3%) मशीन दिवसो के लिए मशीन खराब पड़ी थीं।

(ग) डाक द्वारा तार संदेश भेजने के लिए अधिकतम 24 घंटे का संय लिया जाता है।

(घ) प्रणाली में सुधार लाने के लिए मौजूदा टेलीग्राफ सर्किटों के अनुरक्षण के लिए उपाय किये जा रहे हैं। इलेक्ट्रानिक की बोर्ड (ईकेबी) उपस्करों के उचित अनुरक्षण हेतु ऐनुअल मेन्टीनेंस कंट्रैक्ट (एएमसी) किया जा रहा है। तथापि जब भी आवश्यकता पड़ती है, खराब हो जाने पर उन्हें बदलने के लिए अपने अपने इलेक्ट्रानिक की बोर्ड कंसेट्रेटसर्स (इकेबीसी) केन्द्रों में इलेक्ट्रानिक की बोर्ड (ईकेबी) मशीनें पर्याप्त मात्रा में रखी जाती है।

Investment by National Highways Authority of India in Bot Projects

*6. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether his Minstry has decided in principle to give sweeping powers to the National Highways Authority of India (NHAI) for investments in Build-Oper-ate-Transfer (BOT) projects in its road policy;

(b) If so, the details thereof;

(c) what were the actual funds provided by Government during 1996-97 and 1997-98 to National Highways Authority of India and what are the additional funds likely to be raised from market by NHAI; and

(d) what are the National Highway Projects short-listed by National Highways Authority of India during 1997-98 with a cost of Rs. 80 crores and above particularly in respect of NH-8 (Delhi-Gurgaon) and (Jaipur-Ajmer)?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T. G. VENKAT-RAMAN): (a) and (b) The Central Government has given adequate powers to National Highways Authority of India for taking up projects on Build-Operate-Transfer basis on National Highways. No Projects are held up for want of powers.

(c) During 1996-97, an amount of Rs. 234 crores was provided by the Central Government to National Highways Authority of India. During 1997-98, an amount of Rs. 250 crores has been given to them so far. No funds are proposed to be raised by National Highways Authority of India from the market during the current financial year.

(d) National Highways projects short-listed by National Highways Authority of India during 1997-98 are Delhi-Gurgaon, Surat-Manor, Jaipur-Kishangarh, Gur-gaon-Kotputli and Jaipur bypass (phase I)

Problems Faced by Textile Industry in Exports

*7. DR. ALLADI P. RAJKUMAR: SHRI SANJAY DALMIA:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government have studied and identified the major problems being faced by the textile industry in exports;

(b) if so, the details thereof;